

न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण

अपील संख्या:- 201/2022

श्री दोलाराम पुत्र तारूराम, जाति जाट, निवासी दिलोई, तहसील बिसाउ, जिला झुंझुनूं।

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।
2. श्री औंकारमल पुत्र चिमनाराम, जाति जाट, निवासी दिलोई दक्षिण (उचित मूल्य दुकानदार तहसील बिसाउ, जिला झुंझुनूं।

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 06.10.2022 द्वारा जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं, विभागीय प्रकर 208/2018

उपस्थित :-

1. श्री नेकीराम बुडानिया एवं श्री कंचनसिंह चौधरी, एडवोकेट - अपीलार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण, एडवोकेट- रेस्पोंडेंट सं0 2 की ओर से।
3. श्री विकास कुमार, विभागीय पैरोकार - रेस्पोंडेंट सं0 1 की ओर से।

आदेश

दिनांक:- 21

प्रस्तुत अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 06.10.2022 मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा मिअ0 पर बहस सुनी गई का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया अपीलान्त पीडित शिकायतकर्ता के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि श्री औंकारम मूल्य दुकानदार दिलोई के विरुद्ध उपभोक्ताओं की शिकायते 2008 से लगातार शिकायतें प्राप्त है। इनका व्यवहार खराब बताये जाने के क्रम में पुनः 2018 में अपीलान्त व अन्य अन्य ग्रामवा श्रीमान् जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को प्रार्थना पत्र बाबत शिकायत प्रस्तुत की गई जिस रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा दिनांक 26.03.2018 को उक्त अपीलान्त व अन्य की शिकायत प्रवर्तन निरीक्षक, झुंझुनूं से करवाई गई जिसमें शिकायतकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करने सुरक्षा के पात्र होने के बावजूद गेहूं नहीं देने का आरोप लगाये जाने पर कार्यालय आदेश क्रम दिनांक 26.03.2018 से उक्त औंकारमल का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर कार्यालय 1659 के जरिये नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया तथा जांच दल से जांच करवाई गई 21.06.2018 को प्रवर्तन अधिकारी ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उक्त राशन डीलर के उपभोक्ताओं को एक-एक वर्ष से लम्बी अवधि तक की गेहूं नहीं देना, अमानक कांटे व बाटों से राशन देने की अनियमिततायें पाई। जांच दल प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष स्वयं डीलर ने भी बाटों व अेहूं नहीं देने के तथ्यों को स्वीकार किया। उक्त डीलर के विरुद्ध पूर्व में भी विभागीय संख्या 137/2017 व 155/2017 द्वारा प्रतिभूति राशि जप्त कर डीलर का लाइसेन्स निरस गया। उक्त डीलर के विरुद्ध कुछ वर्ष पूर्व पुलिस थाना बिसाउ में भी राशन सामग्री की अनिय

के कम मे एक प्रथम सूचना रिपोर्ट 91/2009 दिनांक 22.09.2009 को प्रवर्तन निरीक्षक श्री पंचायत समिति अलसीसर द्वारा दर्ज करवाई गई जिसमे पुलिस थाना बिसाउ द्वारा उक्त राश के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं के समक्ष चार्जसीट पेश की तत्पश्चात् दौराने ट्रायल उक्त प्रकरण मे दिनांक 19.12.2018 को उक्त औंकारमल द्वारा प्रकरण संख्या 421/2010 सरकार बनाम औंकारमल अधारा 3/7 ई0सी0 एक्ट मे स्वेच्छ स्वीकार किया जिस पर न्यायालय द्वारा औंकारमल को दोषी माना गया तथा सुधरने का अवसर करते हुए परिवीक्षा का लाभ दिया जाकर जुर्माने से दण्डित किया गया। दिनांक 26.06.2018 प्रकरण मे उक्त औंकारमल की प्रतिभूति राशि जप्त कर लाइसेन्स निलम्बित किया गया। उक्त के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष एक अपील सं0 72/2018 उक्त औंकारमल द्वारा प्रस्तुत थी जो उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 27.08.2018 को निर्णित कर श्रीमान् जि अधिकारी के निर्णय दिनांक 26.06.2018 को यथावत रखकर उक्त औंकारमल की अपील यथावत हुए खारीज कर दी गई। तत्पश्चात् उक्त औंकारमल की अपील न्यायालय अतिरिक्त खादय जयपुर के समक्ष एक पुर्ननिरीक्षण याचिका दायर की गई थी। याचिका के नम्बर 46/2018 याचिका निर्णय दिनांक 28.07.2021 को किया जाकर प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया तथा उक्त याचिका निर्णय मे यह भी आदेश दिया गया कि उक्त प्रकरण संख्या 208/2018 का निर्णय 2 माह के अन्दर मे पारित करें। जिस पर दिनांक 06.10.2022 को उक्त प्रकरण संख्या 208/2018 का निर्णय रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा किया जाकर औंकारमल का प्राधिकार पत्र 787/2000 को बहाल किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है। उक्त अपीलान्त व अन्य व्यक्ति ग्रामवासियान दिलोई द्वारा उक्त औंकारमल के विरुद्ध शिकायत की गई। इस तरह अपीलान्त व ग्रामवासियान पीडित पक्षकार की तारीफ मे आते है। इसलिए शिकायतकर्ताओं की ओर से उक्त अपीलान्त दोलाराम को उक्त आदेश की अपील करने हेतु प्रस्तुत किया गया है इसलिए यह अपील प्रस्तुत करने के लिए उक्त अपीलान्त पीडित पक्षकार होकर अपील करने का अधिकारी है। इसलिए अपील निम्न आधार पर पेश है कि अदालत मातहत का आदेश अमान्य कानून व पत्रावली है। अदालत मातहत का निर्णय महज कयास पर आधारित होकर एक आर्डर की तारीफ मे नही आता है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय मे प्रस्तुत जांच रिपोर्ट व तथ्यों की सन्तुष्टि का कोई आधार दर्ज नही किया है। अदालत मातहत का आदेश स्पष्ट अमान्य है। अदालत मातहत को पत्रावली जिस आधार पर रिमाण्ड की गई उन तथ्यों की जांच व सन्तुष्टि कोई आधार अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे अंकित नही किया है। पूर्व जांच 21.06.2018 से सन्तुष्ट होकर अदालत मातहत ने उक्त डीलर का लाइसेन्स निरस्त किया था वर्तमान जांच से सन्तुष्टि व असन्तुष्टि का क्या आधार रहा है। वर्तमान जांच मे उक्त डीलर को दण्डित किया गया है या नही माना गया इस बाबत भी कोई तथ्य अदालत मातहत ने अपने आदेश मे अंकित किया है। इस तहत अदालत मातहत का निर्णय मनमाना है। जिस डीलर का पूर्व मे तीन बार लाइसेन्स निरस्त हो चुका हो तथा धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट मे प्रस्तुत चालान पुलिस थाना बिसाउ डीलर द्वारा अपना स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया गया हो और न्यायालय द्वारा जिस डीलर को दण्डित मानकर सुधरने का अवसर दिया गया हो उन सभी तथ्यों का मध्य नजर नही रखते हुए वर्तमान

मे जिला सरद अधिकारी की सन्तुष्टि का आधार व एक आदतन अपराध करने वाले डी लाइसेन्स बहाल किये जाने के क्या कारण रहे है उक्त तथ्यों बाबत अदालत मातहत ने अपने कोई सन्तोषप्रद आधार प्रस्तुत नहीं किये। इस प्रकार अदालत मातहत का आदेश प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। दौराने पुनः जांच किसी भी शिकायतकर्ता को ना तो कोई नोटिस जा गया और ना ही सुना गया और ना ही कोई दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य को प्रस्तुत करने का दिया गया। इस प्रकार आलत मातहत द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन कर बिन पक्ष को अवसर दिये मनमाना आदेश पारित किया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है वि अपीलान्त स्वीकार की जाकर अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 06. को निरस्त कर उक्त राशन डीलर का लाइसेन्स निरस्त फरमाया जावे।

बहस सुनी गयी । वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत का निर्णय महज कयास पर आधारित होकर एक आर्डर की तारीफ मे नहीं आता है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय मे प्रस्तुत जांच रिपोर्ट त तथ्यों की सन्तुष्टि का कोई आधार दर्ज नहीं किया है। अदालत मातहत का आदेश स्पष्ट आ है। अदालत मातहत को पत्रावली जिस आधार पर रिमाण्ड की गई उन तथ्यों की जांच व सन कोई आधार अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे अंकित नहीं किया है। पूर्व जांच 21.06.2018 से सन्तुष्ट होकर अदालत मातहत ने उक्त डीलर का लाइसेन्स निरस्त किया था वर्तमान जांच जांच से सन्तुष्टि व असन्तुष्टि का क्या आधार रहा है। वर्तमान जांच मे उक्त डीलर को दो गया है या नहीं माना गया इस बाबत भी कोई तथ्य अदालत मातहत ने अपने आदेश मे अंकित किया है। इस तहत अदालत मातहत का निर्णय मनमाना है। जिस डीलर का पूर्व मे तीन बार निरस्त हो चुका हो तथा धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट मे प्रस्तुत चालान पुलिस थाना बिसाउ डीलर द्वारा अपना स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया गया हो और न्यायालय द्वारा जिस डीलर मानकर सुधरने का अवसर दिया गया हो उन सभी तथ्यों का मध्य नजर नहीं रखते हुए वर्तमान मे जिला सरद अधिकारी की सन्तुष्टि का आधार व एक आदतन अपराध करने वाले डी लाइसेन्स बहाल किये जाने के क्या कारण रहे है उक्त तथ्यों बाबत अदालत मातहत ने अपने कोई सन्तोषप्रद आधार प्रस्तुत नहीं किये। इस प्रकार अदालत मातहत का आदेश प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। दौराने पुनः जांच किसी भी शिकायतकर्ता को ना तो कोई नोटिस जा गया और ना ही सुना गया और ना ही कोई दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य को प्रस्तुत करने का दिया गया। इस प्रकार आलत मातहत द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन कर बिन पक्ष को अवसर दिये मनमाना आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार व अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 06.10.2022 को निरस्त कर उक्त डीलर का लाइसेन्स निरस्त फरमाया जावे।

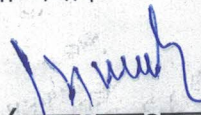
विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान वकील अपीलान्त के कथनों व किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2022 व

नियमानुसार पारित किया गया है। अपीलान्त की यह अपील सारहीन है। अपीलान्त की अपील फोर्स नहीं है। अतः अपील अपीलान्त में कोई फोर्स नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोंडेन्ट सं० २ ने बहस के दौरान वकील अपीलान्त के कथनों का विरोध तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपील मेमो में शुरू में तो अपीलकर्ता दोलाराम को अंकित किया जबकि अन्त में अपीलकर्ता शिवचन्द अंकित किया गया है। अपील मेमो से स्पष्ट नहीं है कि यह दोलाराम द्वारा की गई है या शिवचन्द द्वारा। अपीलान्त की यह अपील प्रोपर नहीं है। अतः अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अपील मेमो से साफ जाहिर है कि अपील मेमो में अपीलकर्ता दोलाराम को अंकित किया गया है जबकि अन्त में अपीलकर्ता शिवचन्द अंकित किया है। अपील मेमो से स्पष्ट नहीं है कि यह अपील दोलाराम द्वारा की गई है या शिवचन्द द्वारा। स्थिति में अपीलान्त की यह अपील प्रोपर नहीं है। अपील प्रोपर नहीं होने से अपील अपीलान्त फोर्स नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है साथ अपीलान्त प्रोपर तरीके से अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र होगा। अतः पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल०एस०कुर्ड)
जिला कलक्टर